छात्रों को मुफ्त बांटे गये टैबलेट्स वापस मांग रही खट्टर सरकार, न लौटाने वालों को रोल नम्बर न देने की धमकी

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) सस्ती एवं फ़र्जी लोकप्रियता पाने के लिये खट्टर सरकार ने सरकारी स्कूलों के नौवीं, दसवीं, ग्यारहवीं व बारहवीं के छात्रों को 5 मई 2022 को खट्टर के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मुफ्त टैबलेट्स बांटकर मीडिया में बड़ी सुर्खियां बटोरी थी। इसके लिये सैंकड़ों करोड़ के टैबलेट्स खरीदने के अलावा लाखों रुपये के विज्ञापन मीडिया को दिये गये थे। अब 9-10 महीने बाद उन टैबलेट्स को छात्रों से वापस लिये जाने के आदेश शिक्षा निदेशालय ने 9 फरवरी को जारी किये हैं। इस आदेश में साफ़ तौर से लिखा गया है कि टैबलेट्स, उसका चार्जर, सिम, यहां तक कि उसका डब्बा भी वापस लिया जाय। डब्बा न होने की स्थिति में शिक्षक को टैबलेट के पीछे मार्कर से आईएमईआई नम्बर लिखना होगा। न लौटाने वाले छात्रों को परीक्षा में बैठने नहीं दिया जायेगा।

कहने को तो ये टैबलेट्स छात्रों के शिक्षा स्तर को बढाने के लिये दिये गये थे। छात्रों एवं शिक्षकों से इस बाबत पूछताछ करने पर पता चला कि किताबों से पढ़ने तथा कक्षा में शिक्षकों द्वारा पढ़ाये जाने की अपेक्षा छात्र खुद-ब-खुद यूट्यूब तथा गूगल आदि से अपनी पढ़ाई कर सकेंगे। शिक्षकों ने यह भी बताया कि अनेकों अभिभावकों ने शिकायत की कि अब उनके बच्चे पढ़ाई लिखाई छोड़ कर हर समय टैबलेट में ही घुसे रहते हैं। वे यूट्यूब और गूगल के माध्यम से क्या-क्या गंद बला देख व सीख रहे हैं, पता ही नहीं चलता। अभिभावक बुरी तरह से परेशान हो कर कहते हैं कि इस टैबलेट ने उनके बच्चे बिल्कुल बिगाड़ दिये हैं।

दरअसल टैबलेट बांटने के पीछे सरकार का उद्देश्य छात्रों का उत्थान करना नहीं था। असल उद्देश्य तो 8 हजार रुपये के टैबलेट की खरीदारी 17 हजार में दिखा कर मोटा माल मारना रहा है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार खट्टर के जन्मदिन पर उपहार स्वरूप ये टैबलेट्स केवल 10वीं तथा 12वीं के बच्चों को ही दिये गये थे, परन्तु मोटी लूट कमाई से उत्साहित होकर बाद में 9वीं तथा 11वीं के बच्चों को भी ये टैबलेट्स बांटे गये थे। यद्यपि इस खरीदारी से सम्बन्धित खर्चे की तमाम फाइलों को छिपा कर रखा गया है। जानकारों का अनुमान है कि इस पर सरकार का 1100 करोड़ रुपये खर्च दिखाया गया है। बच्चों को पढ़ाने के लिये शिक्षक भर्ती नहीं करेंगे, आवश्यक फर्नीचर, लाइब्रेरी, लैबोरेट्री आदि उपलब्ध कराने की अपेक्षा कभी एजुसेट, उसे चलाने के लिये जनरेटर सेट तो अब टैबलेट्स बांटने जैसे काम कर सकते हैं।

इसके अलावा शिक्षा विभाग का पैसा डकारने के लिये स्कूलों में बच्चों के बस्ते रखने के लिये 'पिजन होल', बनाने के लिये करोड़ों रुपये डकारे जा चुके हैं। इसी तरह समय-समय पर स्कूलों में चित्रकारी कराने के नाम पर फर्जी बिलों द्वारा करोड़ों के भुगतान डकारे गये हैं।

यहां एक और समझने वाली बात यह भी है कि जब बच्चों को टैबलेट से ही पढ़ाई करनी है तो परीक्षा से महीनों पहले उनके वापस लेने का क्या मतलब? यदि बच्चे वास्तव में ही टैबलेट से ही पढ़ाई कर रहे हैं तो परीक्षा शुरू होने से पहले टैबलेट वापस लेने का क्या मतलब? इन्हें वापस देने के बाद बच्चे कैसे पढ़ाई कर पायेंगे?

टैबलेट्स बांटने के बाद अब उन्हें वापस लेने को लेकर, राज्य भर के तमाम प्रधानाचार्य तथा सम्बन्धित शिक्षक बुरी तरह से परेशान हैं। बच्चों को पढ़ाने-लिखाने का काम तो उनसे बहुत पहले ही ले लिया गया था अब ये नया काम और उन्हें सौंप दिया गया है। इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि टैबलेट लेने वाले सारे बच्चे स्कूल से जुड़े ही रहें, न जाने कब कौन बच्चा स्कूल छोड़ जाये। कितने बच्चों ने अपने टैबलेट को सही ढंग से सम्भाल कर रखा होगा, कहा नहीं जा सकता।

बच्चों द्वारा लापरवाही के चलते इसका टूट-फूट जाना कोई नई बात नहीं। यह भी पता चला है कि अनेकों बच्चों ने टैबलेट के साथ मिले सिम को फेंक कर अपना सिम डाल लिया है। ऐसे में अब क्या तो प्रधानाचार्य करेगा और क्या आचार्य करेगा। और तो और इन वापस आने वाले टैबलेटों को सम्भाल कर रखना भी इन्हीं आचार्यों की जिम्मेवारी रहेगी। अपर्याप्त स्टाफ़, तथा असुरक्षित स्कूल बिल्डिंग के चलते, स्टाफ़ के लिये यह एक नई मुसीबत खड़ी होनेवाली है।

एसीएस महावीर सिंह का आखिरी छक्का

लूट कमाई को लेकर शिक्षा विभाग भी किसी अन्य भ्रष्ट विभाग से पीछे रहने को तैयार नहीं। अंतर केवल इतना ही है कि इस विभाग में लूट कमाई सीधे जनता से न होकर, सरकारी खजाने से होती है। इस लूट का पूरा नियंत्रण एवं दिशा निर्देशन विभाग के एसीएस द्वारा होता है।

इस विभाग के एसीएस महावीर सिंह हैं। वे 28 फरवरी को सेवा मुक्त हो जायेंगे। यानी कि इस तिथि के बाद वे टैबलेट्स जैसी और कोई खरीदारी नहीं कर पायेंगे। इसलिये कहा जा सकता है कि यह खरीदारी उनके सेवाकाल का अन्तिम छक्का रहा है।

इस छक्के के अलावा पूरे शिक्षा विभाग में जो भ्रष्टाचार का खेल खेला जाता रहा है उसमें भी उनके दुक्के-चौके लगते रहे हैं। हर ज़िले में स्कूलों की बिल्डिंग निर्माण के जो फ़र्जीवाड़े होते रहे हैं वे उनकी मर्जी एवं मिलीभगत के बिना सम्भव नहीं थे। हर स्तर पर जो घपले होते रहे हैं वे भी मिलीभगत के बगैर सम्भव नहीं। लूट-मार के अपने इस कारोबार के लिये उन्होंने अपने दफ्तर में बाकायदा दो जमूरे तैनात कर रखे थे। जो स्कूलों में न पढ़ा कर इनके लिये लूट कमाई की नई-नई योजनायें प्रस्तुत करने में विशेष महारत रखते थे।

अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते हुए राष्ट्रीय बजट को लेकर भाजपाईयों ने अपनी पीठ थपथपाई

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) लूट कमाई से बने, सेक्टर 15 स्थित ज़िला भाजपा कार्यालय में बीते सप्ताह एक बैठक का आयोजन हुआ। इसमें आर्थिक प्रकोष्ट की भाजपा प्रदेश संयोजिका रश्मि खेत्रपाल, जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा, जिला महामंत्री मूलचंद मित्तल और जिला संयोजक डीसी गर्ग ने बजट पर विचार रखते हुए बताया कि हाल ही में निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया बजट अमृतकाल का पहला बजट है। जिसमें आगामी 25 साल का रोडमैप रखा गया है।

झूठ बोलने में माहिर इन भाजपाईयों की बड़ी विचित्र बात है कि ये पेश तो करते हैं एक साल का बजट और उसमें बातें करते हैं 25 साल की या पांच साल की। वित्तमंत्री सीतारमण ने तो बजट भाषण के दौरान देश भर में एकलव्य स्कूलों की बात करते हुए आगामी तीन साल में 38 हजार शिक्षक भर्ती करने की बात कही है। है न कमाल की बात। तीन साल की बात करती हैं वे, ये नहीं बताती कि इस एक साल में

कितने शिक्षक भर्ती करेंगी? इसमें पेच यह है कि आगामी तीन साल तक उनसे कोई यह न पूछे कि कहां हैं वे 38 हजार शिक्षक। इसी तर्ज पर 2015 में मोदी ने 2022 तक किसानों की आय दोगुणी करने की बात कही थी, यानी कि 2022 तक इस बाबत उनसे कोई सवाल न किया जाय। इसी तरह सबके सिर पर छत और सबके घरों में शौचालय और न जाने कितने तरह के वायदे उन्होंने कर डाले थे, जो आज तक एक भी पूरा नहीं हुआ। अब वे बात करने लगे हैं आगामी 25 साल की यानी कि 2047 तक उनसे कोई सवाल न पूछा जाय।

इस मंडली ने बताया कि किसानों, युवाओं, वंचितों आदि को प्रोत्साहित एवं लाभान्वित करने के लिये बजट में बहुत प्रावधान किये हैं। किसानों को प्रोत्साहित करने का जवाब तो किसान आन्दोलन दे ही रहे हैं। इन्फ्रास्ट्रक्चर की हालत देखने के लिये कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, इसी शहर की टूटी सड़कें, सड़कों पर बहता सीवर, पेयजल का संकट, सरकारी स्कूलों की जर्जर इमारतों से ही देखा जा सकता है। रही-सही कसर को सड़कों पर टोल के नाम पर हो रही लूट के रूप में भी देखा जा सकता है।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में बखान करते हुए ये लोग बताते हैं कि एमबीबीएस की यानी यूजी की सीटें मोदी जी ने 51 हजार से 99 हजार कर दी हैं। कोई पूछे इन झूठे मक्कारों से कि इसके लिये वास्तव में सरकार ने किया क्या? कुछ भी तो नहीं। उदाहरण के लिये स्थानीय ईएसआई मेडिकल कॉलेज में 100 की जगह 125 सीटें घोषित कर दी गई, लेकिन इन बढी हुई सीटों के लिये सरकार ने किया क्या? इसके लिये न तो कोई फैकल्टी बढाई और न ही कोई हॉस्टल की सुविधा। यदि इस तरह ही सीटें बढानी है तो 99 हजार क्या दो लाख भी कर दो। देश भर की बात तो छोड़िये हरियाणा के 6 मेडिकल कॉलेजों में फैकल्टी के कुल 982 पद पिछले कई वर्षों से खाली पड़े हैं। छांयसा वाले मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जिस पर बीते चार साल से हरियाणा सरकार का कब्जा है, में अभी तक ओपीडी शुरू नहीं हो पाई है, बातें करते हैं लम्बी-लम्बी।

अब आ जाइये पीजी यानी एमबीबीएस के बाद वाली स्नातकोत्तर पढ़ाई पर। ये दावा करते हैं कि 34 हजार से बढ़ाकर 67 हजार करने की। लेकिन यह नहीं बताते कि इसमें सरकार ने क्या किया? सर्वविदित है कि पीजी की सीटें प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की लूट कमाई का मुख्य जरिया है। एक-एक सीट दो से तीन करोड़ तक में बिकती है। यह बताने की जरूरत नहीं रह गई है कि जब सरकारी मेडिकल कॉलेजों में ही फैकल्टी पूरी नहीं है तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में फैकल्टी की क्या हालत होगी? ऐसे में यानी जहां न तो पर्याप्त फैकल्टी हो और न ही अस्पताल तो वहां से पीजी की डिग्री लेकर निकलने वाले कैसा इलाज करेंगे?

शेखचिल्ली की तरह आगामी 10-20-25 साल तक के अनेकों टारगेट घोषित करते हुए भले ही इन लोगों ने अपनी पीठ थपथपा ली हो लेकिन इनका बीते नौ वर्ष का चाल-चरित्र, चेहरा तथा वायदों को देखते हुए आसानी से समझा जा सकता है कि ये निरे झूठे हैं। आगामी घोषित तिथियां आने पर ये अपने पुराने वायदों का जिक्र भी कभी नहीं करेंगे जैसे कि अब 15 लाख का कोई जिक्र नहीं करते, दो करोड़ सालाना नौकरियों का कोई जिक्र नहीं करते, काला धन समाप्त करने की कोई बात नहीं करते, महंगाई घटाने आदि-आदि की कोई बात नहीं करते।

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में एजीएस पब्लिकेशन्स, डी-67, सैक्टर-6, नोएडा से मुद्रित करवा कर 708 सैक्टर-14 फरीदाबाद से प्रकाशित किया।